



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 26—फरवरी 1, 2019 (माघ 6, 1940)  
 No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 26—FEBRUARY 1, 2019 (MAGHA 6, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	19	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	69	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	245	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 205
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 3
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 85
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	19	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	69	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	245	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	205
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	3
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	85
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

**भाग I—खण्ड 1****[PART I—SECTION 1]**

**[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]**

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-01, दिनांक 4 जनवरी 2019

सं. एफ. 9-4/97-यू.3—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 10.09.1999 की अधिसूचना सं. 9-4/97-यू.3 के जरिए आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से समविश्वविद्यालय घोषित किया था।

3. और जबकि, रजिस्ट्रार, आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे ने दिनांक 23.07.2018 को "आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान" का नाम बदलकर "उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान" करने का अनुरोध किया था।

4. और जबकि, इस मंत्रालय द्वारा यूजीसी के परामर्श से मामले पर विचार किया गया है, यूजीसी ने सत्यापन के बाद निम्न सूचना दी है:

- i. सोसाइटी का नाम बदल दिया गया है जोकि उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान सोसाइटी है।
- ii. समविश्वविद्यालय की सारी परिसंपत्तियों को कानूनी रूप से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), भारत सरकार के नाम कर दिया गया है। डीआरडीओ ने संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है कि गिरिनगर, पुणे परिसर की चल और अचल परिसंपत्तियों का उपयोग समविश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, यूजीसी के परामर्श से एतदद्वारा यह अधिसूचना जारी करके इसका नाम 'आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान' को प्रतिस्थापित करके उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान करती है। उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान, पुणे महाराष्ट्र नाम के बाद विश्वविद्यालय प्रत्यय नहीं जोड़ा जाएगा किंतु वह अपने नाम के बाद प्रत्यय के रूप में कोष्ठक में समविश्वविद्यालय लिख सकता है।

6. इस मंत्रालय की समय-समय पर जारी पूर्व की अधिसूचनाओं में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों और यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के मानकों/विनियमों का अनुपालन उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान, पुणे महाराष्ट्र द्वारा किया जाएगा।

ईशिता राय  
संयुक्त सचिव

दिनांक 7 जनवरी 2019

सं. एफ. 9-65/2006-यू.3(ए) भाग.1—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 12.06.2007 की अधिसूचना सं. 9-65/2006-यू.3(ए) द्वारा "महर्षि मार्कण्डेय विश्वविद्यालय, मुलाना, अंबाला हरियाणा" जिसमें निम्नलिखित संस्थाएं शामिल हैं, पांच वर्षों के बाद समीक्षा के अध्यधीन समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया था;

- i. एम.एम. इंजीनियरिंग कॉलेज, मुलाना, अंबाला;
- ii. एम.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट (एमसीए), मुलाना, अंबाला;
- iii. एम.एम. कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च, मुलाना, अंबाला;
- iv. एम.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथैरेपी एंड रिहैबिलिटेशन, मुलाना, अंबाला;
- v. एम.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट (होटल मैनेजमेंट), मुलाना, अंबाला;
- vi. एम.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, मुलाना, अंबाला;
- vii. एम.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मुलाना, अंबाला;
- viii. एम.एम. कालेज ऑफ नर्सिंग, मुलाना, अंबाला;
- ix. एम.एम. कालेज ऑफ फार्मसी, मुलाना, अंबाला; और
- x. एम.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च नर्सिंग कॉलेज, मुलाना, अंबाला।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 03.11.2017 की सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 में यह निर्णय दिया था कि यूजीसी, यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन के लिए उचित कदम उठाएगा और समविश्वविद्यालयों को 'विश्वविद्यालय' शब्द का उपयोग करने से रोकेगा।

4. और जबकि, केन्द्र सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार और यूजीसी के परामर्श से यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11.01.2018 की अपनी अधिसूचना सं. 9-65/2006-यू3(ए) के तहत "महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय" के नाम से "विश्वविद्यालय" शब्द को हटाकर उसका नाम "महर्षि मार्कंडेश्वर" इस शर्त के साथ करती है कि महर्षि मार्कंडेश्वर, मुलाना, अम्बाला अपने नाम के बाद "विश्वविद्यालय" प्रत्यय शब्दों का उपयोग नहीं करेगा लेकिन आगे कोष्ठकों के भीतर "समविश्वविद्यालय" प्रत्यय शब्द का उपयोग कर सकता है।

5. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी द्वारा अपनी विशेषज्ञ समिति की सहायता से दिनांक 8-10 अगस्त, 2018 के दौरान महर्षि मार्कंडेश्वर, मुलाना, अंबाला के कार्यों की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आयोग के समक्ष दिनांक 27.09.2018 को आयोजित अपनी 535वीं बैठक (मद सं. 2.02) में रखी गई थी। समिति ने सिफारिश की है कि महर्षि मार्कंडेश्वर, मुलाना, अंबाला के समविश्वविद्यालय दर्जे को जारी रखा जाए। आयोग ने अपनी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

6. और जबकि, यूजीसी की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ यूजीसी की सिफारिशों की मंत्रालय में जांच की गई थी और निम्नलिखित पाया गया:

- क) समविश्वविद्यालय ने यूजीसी विनियमों के विरुद्ध यूजीसी के अनुमोदन के बिना विधि पाठ्यक्रम शुरू किया है।
- ख) सभी संकाय सदस्यों के एच-इंडेक्स और उद्धरण आशाजनक स्तर से नीचे हैं।
- ग) समविश्वविद्यालय संस्थान के संकायों द्वारा प्रकाशित कई पुस्तकें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक संख्या मानक (आईएसबीएन) द्वारा सूचीबद्ध नहीं हैं।

7. अब, जबकि, केंद्र सरकार यूजीसी के परामर्श से, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महर्षि मार्कंडेश्वर, मुलाना, अंबाला, हरियाणा को दिनांक 12.06.2012 से 30.06.2020 तक, समविश्वविद्यालय दर्जे को निम्नलिखित शर्तों के साथ आगे बढ़ाती है:

- क) समविश्वविद्यालय यूजीसी के अनुमोदन के बिना आगे विधि पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।
- ख) समविश्वविद्यालय संकाय सदस्यों के एच-इंडेक्स और उद्धरण के माध्यम से अपने एनएएसी स्कोर में सुधार करेगा।
- ग) समविश्वविद्यालय यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों/कमियों के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

8. महर्षि मार्कंडेश्वर, मुलाना, अंबाला, हरियाणा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ, यूजीसी और अन्य संविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों का अनुपालन करता रहेगा।

ईशिता राँय  
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 9-28/2009-यू.3(ए)खंड-1—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 08.05.2012 की अधिसूचना सं. 9-28/2009-यू3(ए) के तहत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षुता एवं प्रबंध संस्थान, (एनआईएफटीईएम) कुंडली, सोनीपत, हरियाणा को, विशेषज्ञ समिति की सहायता से यूजीसी द्वारा पांच वर्ष की वार्षिक समीक्षा के अध्यक्षीन, डी-नोवो श्रेणी के अंतर्गत सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया था।

3. और जबकि, यूजीसी ने अपनी विशेषज्ञ समिति की सहायता से 12 से 13 जुलाई, 2018 के दौरान एनआईएफटीईएम, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा की कार्यपद्धति की समीक्षा की थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को आयोग की दिनांक 02.08.2018 को आयोजित 524वीं बैठक (मद सं.2.07) में प्रस्तुत किया गया था जिसमें आयोग ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया था :

"यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद आयोग ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षुता एवं प्रबंध संस्थान (एनआईएफटीईएम), कुंडली, सोनीपत, हरियाणा को दो वर्षों, 2020 तक समवत विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने हेतु एमएचआरडी से सिफारिश करने का संकल्प लिया था। समवत विश्वविद्यालय संस्थान से दो वर्ष के भीतर एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त करने और इस अवधि के दौरान अनुपालना रिपोर्ट यूजीसी को प्रस्तुत करने को कहा जा सकेगा"

4. अब, इसलिए, केन्द्र सरकार एतद द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर एतद द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षुता एवं प्रबंध संस्थान, (एनआईएफटीईएम) कुंडली, सोनीपत, हरियाणा को दिनांक 08.05.2017 से 30.06.2020 तक निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन समवत विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करती है:

क) समवत विश्वविद्यालय प्रत्यायन हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से तत्काल सम्पर्क करेगा।

ख) समवत विश्वविद्यालय यूजीसी विश्वविद्यालय समिति द्वारा दिए गए सुझावों/विसंगतियों के संदर्भ में अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

5. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षुता एवं प्रबंध संस्थान, (एनआईएफटीईएम), कुंडली, सोनीपत, हरियाणा इस मंत्रालय की पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों में उल्लिखित शर्तों का पालन करता रहेगा।

ईशिता रॉय  
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-01, the 4th January 2019

No. F.9-4/97-U.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-4/97-U.3 dated 10.09.1999, on the advice of UGC, had declared Institute of Armament Technology, Pune as an Institution deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect.

3. And whereas, Registrar, Institute of Armament Technology, Pune on 23.07.2018 submitted a request for change of name of the Institution from “Institute of Armament Technology” to “Defence Institute of Advanced Technology”.

4. And whereas, the matter has been considered by this Ministry in consultation with UGC. UGC, after verification, has informed the following:

- i. The name of the Society has been changed in the new name i.e. Defence Institute of Advanced Technology Society.
- ii. All assets of the Deemed to be University are legally registered in the name of Defence Research & Development Organization (DRDO), Government of India. DRDO has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Institution that the moveable and immoveable assets at Girinagar, Pune Campus will be utilized by the Deemed to be University.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby change the name of “Institute of Armament Technology” to “Defence Institute of Advanced Technology” w.e.f. the issuance of this Notification. Defence Institute of Advanced Technology, Pune, Maharashtra shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the word “deemed to be university” within parenthesis suffixed thereto.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Norms/Regulations of UGC and Statutory Council(s) concerned, issued from time to time, shall continue to be adhered by Defence Institute of Advanced Technology, Pune, Maharashtra.

ISHITA ROY  
Joint Secretary

\_\_\_\_\_  
The 7th January 2019

No. F.9-65/2006-U3(A)Pt.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-65/2006-U3(A) dated 12.06.2007, on the advice of UGC, had declared Maharishi Markandeshwar University, Mullana, Ambala, Haryana as an Institution deemed to be University consisting of the following Institutions, subject to review after five years:

- i. MM Engineering College, Mullana, Ambala;
- ii. MM Institute of Computer Technology & Business Management (MCA), Mullana, Ambala;
- iii. MM College of Dental Sciences & Research, Mullana, Ambala;
- iv. MM Institute of Physiotherapy & Rehabilitation, Mullana, Ambala;
- v. MM Institute of Computer Technology & Business Management (Hotel Management), Mullana, Ambala;
- vi. MM Institute of Medical Sciences & Research, Mullana, Ambala;
- vii. MM Institute of Management, Mullana, Ambala;
- viii. MM College of Nursing, Mullana, Ambala;
- ix. MM College of Pharmacy, Mullana, Ambala; and
- x. MM Institute of Medical Sciences & Research Nursing College, Mullana, Ambala.

3. And further whereas, the Hon'ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and will restrain Deemed to be Universities from using the word 'University'.

4. And whereas, as per direction of Hon'ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, change the name of "Maharishi Markandeshwar University" to "Maharishi Markandeshwar" by deleting the word 'University' from its name vide its Notification No. 9-65/2006-U3(A) dated 11.01.2018 with the condition that Maharishi Markandeshwar, Mullana, Ambala shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the word "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

5. And further whereas, the functioning of Maharishi Markandeshwar, Mullana, Ambala was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 8-10th August, 2018. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 535th meeting (Item No.2.02) held on 27.09.2018. The Committee recommended that the Deemed University status to Maharishi Markandeshwar, Mullana, Ambala may be continued. The Commission considered and approved the report of its Expert Committee.

6. And whereas, the report of the UGC Expert Committee as well as recommendations of UGC was examined in the Ministry and observed the following:

- a) The Deemed to be University has started Law Course without approval of the UGC in contrary to the UGC Regulations.
- b) The h-index and citations of all faculty members are below the expectation levels.
- c) Many of the books published by the faculty of the Institution Deemed to be University are not indexed by International Standard Book Number (ISBN).

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to Maharishi Markandeshwar, Mullana, Ambala, Haryana from 12.06.2012 to 30.06.2020 with the following conditions:

- a) The deemed to be University shall henceforth not admit students in Law Course, without approval of the UGC.
- b) The deemed to be University shall improve its NAAC score through its h-index and citations of the faculty members.
- c) The deemed to be University shall submit compliance report w.r.t. suggestions/deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

8. All the other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules/Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Maharishi Markandeshwar, Mullana, Ambala, Haryana.

ISHITA ROY  
Joint Secretary

---

No. F.9-28/2009-U3(A)Pt.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-28/2009-U3(A) dated 08.05.2012, declared National Institute of Food Technology, Entrepreneurship & Management (NIFTEM), Kundli, Sonapat, Haryana as an Institution deemed to be University under de-novo category, subject to annual review for 5 years by UGC with the help of Expert Committee.

3. And whereas, the functioning of NIFTEM, Kundli, Sonapat, Haryana was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 12-13th July, 2018. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 534th meeting (Item No.2.07) held on 02.08.2018. The Commission passed the following resolution:

"The Commission considered the report of the UGC Expert Committee and resolved to recommend to MHRD for Deemed to be University status to National Institute of Food Technology, Entrepreneurship & Management (NIFTEM), Kundli, Sonapat, Haryana for 2 years till 2020. The Institution Deemed to be University may be asked to get NAAC accreditation within two years and submit compliance report to UGC during this period."

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to National Institute of Food Technology, Entrepreneurship & Management (NIFTEM), Kundli, Sonapat, Haryana from 08.05.2017 to 30.06.2020 with the following conditions:

- a) The deemed to be University shall immediately approach National Assessment and Accreditation Council (NAAC) for accreditation.
- b) The deemed to be University shall submit a compliance report w.r.t. suggestions/deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

5. All the other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules/Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by National Institute of Food Technology, Entrepreneurship & Management (NIFTEM), Kundli, Sonapat, Haryana.

ISHITA ROY  
Joint Secretary